सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 309 राँची, बुधवार, 6 मई, 2026 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

30 अप्रैल, 2026

संख्या- 02/भा°व°से° (स्था°)- 03/2018- 1629--दिनांक 29.08.2016 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री आर°आर° हेम्ब्रम, भा°व°से° (झा°-83) की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के पद पर नियुक्ति की गई थी। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध श्री प्रदीप कुमार, दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत भा°व°से° (झा°-82) द्वारा माननीय Central Administrative Tribunal, Patna Bench, Circuit Bench Ranchi में एक वाद संख्या- OA/051/00132/2016 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक-24.05.2017 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया-

"In view of the aforesaid facts, we are constrained and compelled to conclude that Sri R.R. Hembrom was not holding the post of PCCF and thus not eligible to be considered for HoFF when the SCM took place at about 3.30 PM on 29.08.2016. Consequently, in our considered opinion, the applicant was the sole eligible candidate for selection as HoFF at that time.

In conclusion, the selection committee proceeding dated 29.08.2016 for HoFF and consequent notification No. 4106 dated 01.09.2016 selecting and notifying Shri R.R. Hembrom to

the post of HoFF in the pay scale of Rs. 80,000/- (Fixed) are quashed and set aside as being illegal as he was not eligible for the post. The respondent State of Jharkhand is at liberty to convene a Selection Committee meeting for selection to this post as per law. Since the applicant has retired in the meanwhile, the respondent authorities are directed to consider granting him notional benefit and pension fixation in the Apex Pay Scale, if found suitable as on 29.08.2016. No order as to costs."

2. माननीय न्यायाधिकरण के उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में दिनांक-05.07.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में दिनांक 29.08.2016 को श्री हेम्ब्रम के अलावा शेष योग्य पदाधिकारियों, जिनमें श्री प्रदीप कुमार का नाम भी शामिल था, पर विचार किया गया था। श्री कुमार की वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक की अवधि में एक ए°सी°आर° की अभ्युक्ति (स्कोर- 7) आउटस्टैंडिंग की श्रेणी में नहीं आने एवं उन्हें 06.05.2011 को निन्दन का दण्ड अधिरोपित होने के दृष्टिपथ उक्त पद के चयन हेतु योग्य नहीं माना।

3. समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि श्री कुमार दिनांक-29.08.2016 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं थे। एतद् विषयक विभागीय आदेश ज्ञापांक-2928, दिनांक-17.07.2017 के द्वारा निर्गत आदेश की प्रति श्री कुमार को भी प्रेषित की गई।

4. श्री कुमार द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या- 2928, दिनांक-17.07.2017 को quash करने तथा उन्हें दिनांक-29.08.2016 के प्रभाव से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान में Notionally select कर तद्नुसार उनके पेंशन को संशोधित करने के संबंध में माननीय Central Administrative Tribunal (CAT), Patna Bench, Circuit Bench Ranchi में एक वाद सं°- OA/051/00130/2017दायर किया गया।

5. माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त वाद में दिनांक-10.08.2018 को पारित आदेश का ऑपरेटिव पार्ट निम्नवत् हैं:-

"12. Be that as it may, the applicant has already superannuated from service on 30.09.2016. Even if it is held that he has been unfairly ignored for the post of PCCF (HOFF), he cannot be brought back to the said post now. We, therefore, feel that ends of justice would be met only by allowing the applicant at least the pensionary benefits commensurate with the pay scale of PCCF (HOFF).

13. In the conspectus of the discussions in the foregoing paragraphs, the impugned order dated 17.07.2017 (Annexure A/2) is quashed and set aside. The respondents are directed to fix the pension of the applicant in the pay scale of PCCF (HOFF) i.e. Rs. 80,000 (Fixed) Pre-revised. We also direct that the applicant shall be given all consequential retiral benefits but without any interest.

14. The directions contained in para (13) shall be complied with by the respondents within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order.

15. The OA is disposed of accordingly. No order as to costs."

6. उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त करते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में अपीलवाद संख्या- WP(S) No. 6206/2018दायर किया गया।

7. श्री प्रदीप कुमार द्वारा OA/051/00130/2017 में माननीय CAT द्वारा दिनांक-10.08.2018 को पारित आदेश के क्रम में CAT में अवमानना वाद- CP No.-89/2018 दायर किया गया।

8. WP(S) No. 6206/2018में दिनांक-05.02.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैंः-

"15. Selection Committee dated 17.07.2017 is that the competency and specific suitability for the post has been overshadowed by absence of outstanding merit and absolute integrity. 'Absolute Integrity' in the context of the selection would mean a high degree of integrity with moral and ethical values of the highest quality and non-compromising level of honesty accompanying the centre stage. As we have noticed above there is not much difference between the capability and competency of the respondent no. 1 and Sri A.K. Prabhakar in the context to the selection for the post of Principal Chief Conservator of Forest (HoFF) and in some of the APR's, the respondent no. 1 outshines and outweighs Sri A.K. Prabhakar. The only bottleneck seems to be the punishment of Censure imposed upon the respondent no. 1 which was also with effect from the year 1994 and which with the passage of time has lost its force. The respondent no. 1, therefore, fulfills the initial two conditions and such findings would automatically trigger his competence and suitability for the post of Principal Chief Conservator of Forest (HoFF).

16. The learned Central Administrative Tribunal in the impugned order dated 10.08.2018 has considered the relevant issues in its proper perspective and have accordingly quashed the decision of the Selection Committee as contained in Memo No. 2928 dated 17.07.2017 with a further direction to fix the pension of the respondent no. 1 in the Pay scale of Principal Chief Conservator of Forest (HoFF) along with all consequential retiral benefits but without any interest. We do not find any reason to cause interference in such findings and consequently we dismiss this writ application.

17. Pending I.A.s, if any, stands closed.

9. विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave Petition दायर किया गया, जिसका डायरी संख्या- 38560/2025 हैं। वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-14.11.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया हैं-

2. Delay condoned.

3. We have heard learned counsel for the parties.

4. Having considered the contentions made across the Bar, we do not find any reason to grant Special Leave to Appeal.

5. As such, the present Special Leave Petition is dismissed, leaving the question of law open.

6. Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

10. श्री प्रदीप कुमार, भा॰व॰से॰ (सेवानिवृत) के संबंध में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड, राँची तथा लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची से अद्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं। साथ ही आंतरिक आरोप की अद्यतन स्थिति भी प्राप्त हैं। श्री प्रदीप कुमार के विरूद्ध सम्प्रति कोई आरोप यथा-जांच/काण्ड/अभियोजन/विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित नहीं हैं।

11. झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रदीप कुमार, सेवानिवृत भा॰व॰से॰ पदाधिकारी को उनकी सेवानिवृति की तिथि-30.09.2016 के प्रभाव से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिना किसी ब्याज के भुगतान का आदेश दिया जाता हैं।

12. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक-28.04.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 10 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी॰,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 309 - 50